कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर – 342001
email-jdanic-jod-rj@nic.in वेब–साईट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086 / 2656357 Fax 021-2612086

कमांक / बैठक / 2020 / भाग(9) / 1025 दिनांक :: 13 अप्रैल, 2022

बैठक कार्यवाही विवरण

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की बैठक दिनांक 13 अप्रैल, 2022 को प्रातः 11.00 बजे श्री (डॉ) राजेश शर्मा, आई.ए.एस., संभागीय आयुक्त एवं अध्यक्ष महोदय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में उपस्थित सदस्यों / अधिकारियों की सूची परिशिष्ट–1 पर संलग्न है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गये:–

प्रस्ताव संख्या 1 :: परिचालन प्रस्ताव दिनांक 17.11.2021 मे लिये गये निर्णयों की पुष्टि।

परिचालन प्रस्ताव दिनांक 17.11.2021 का कार्यवाही विवरण जारी किया जा चुका है। अतः परिचालन प्रस्ताव दिनांक 17.11.2021 का कार्यवाही विवरण पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से परिचालन प्रस्ताव दिनांक 17/11/2011 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन करते हुए लिये गये निर्णय की पुष्टि करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 2 :: नगर निगम दक्षिण के जोनल डवलपमेंट प्लान को अन्तिम रूप दिये जाने के संबंध में।

जोधपुर शहर के मास्टर डवलपमेंट प्लान 2031 क्षैत्र के जोनल डवलपमेंट प्लान बनाये जाने के कम में नगर निगम दक्षिण, जोधपुर का जोनल डवपलमेंट प्लान प्रारूप तैयार किया जाकर इसके प्रारूप पर आमजन से आपत्ति / सुझाव आमंत्रित करने हेतु दिनांक 19.11.2021 को अधिसूचना का प्रकाशन किया गया। जिसके क्रम में प्राप्त आपत्ति / सुझावों का विश्लेषण कर नगर निगम–दक्षिण द्वारा कार्यपालक समिति की बैठक दिनांक 22.12.2021 को आयोजित की गई। उक्त समिति की रिपोर्ट जरिये पत्रांक 2601 दिनांक 24.12.2021 को प्राधिकरण में प्राप्त हुई। नगर निगम दक्षिण जोन के प्रारूप पर प्राप्त आपत्तियों के संबंध में नगर निगम दक्षिण द्वारा तैयार रिपोर्ट पर विचार कर नगर निगम दक्षिण जोन के जोनल डवपलमेंट प्लान को अंन्तिम रूप दिये जाने हेतु जोधपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्ताव संख्या 04 अवलोकनार्थ एवम् विचारार्थ रखा गया। जोधपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 30.12.2021 के कार्यवाही विवरण अनुसार प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

"बैठक में निदेशक–आयोजना ने इस संबंध में नगर निगम, जोधपुर–दक्षिण द्वारा प्रस्तुत आपत्ति सुझावों के निस्तारण संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत की। जो इस कार्यवाही का भाग परिशिष्ट–3 है। बैठक में प्रस्तुत आपत्ति / सुझावों पर विचार विमर्श कर निम्नलिखित आपत्तियों के संबंध में निर्णय लेते हुए शेष रिपोर्ट का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

1. आपत्ति संख्या–4, 12, 14, 16, 17, 18, 24, 26, 27, 28, 39 एवं 43 (आपत्तिकर्ता श्री विमलेश एवं अन्य) के संबंध में निर्णय लिया गया कि रातानाड़ा से सर्किट हाऊस तक सडक के मार्गाधिकार बाबत् नगर निगम दक्षिण द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार इस सडक की विद्यमान चौड़ाई व इस सडक पर हुऐ पूर्व कमिटमेन्ट के आधार पर इसका मार्गाधिकार 100'–120' रखे जाने का प्रस्ताव दिया है। अतः नगर निगम–दक्षिण के

प्रस्ताव, विद्यमान मार्गाधिकार एवं सडक मार्गाधिकार पर विद्यमान भवन रेखाओं के दृष्टिगत रातानाड़ा भाटी सर्कल से गणेश मंदिर तिराहा तक सड़क का मार्गाधिकार 120 फीट एवं गणेश मंदिर तिराहा से सर्किट हाउस तक मास्टर प्लान अनुसार सडक मार्गाधिकार यथावत् रखा जाना प्रस्तावित है।

2. आपत्ति संख्या–5 व 13 (आपत्तिकर्ता श्री सूरज कुमार एवं अन्य) के संबंध में निर्णय लिया गया कि पांचवी रोड चौराहा से बारहवीं रोड चौराहा तक सडक का मार्गाधिकार बाबत् नगर निगम दक्षिण द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में मौके पर उपलब्ध मार्गाधिकार व 12वी रोड से पावटा सर्किल तक पूर्व में निर्धारित सडक मार्गाधिकार के दृष्टिगत 100'–120' फीट रखा जाना प्रस्तावित किया है। अतः नगर निगम के प्रस्ताव व सडक की समरूप निरन्तरता के दृष्टिगत इस सडक का मार्गाधिकार 120' रखा जाना प्रस्तावित है।

3. आपत्ति संख्या–6 (आपत्तिकर्ता श्री हनुमान प्रसाद तोषनीवाल) के संबंध में यह निर्णय लिया गया कि मौके पर अवस्थित सरकारी, अर्द्ध सरकारी कार्यालय परिसर की सीमा का सही अंकन कर शेष भूमि का भू–उपयोग जोनल डवलपमेन्ट प्लान में समीपीय उपयोग अनुसार दर्शाया जाना प्रस्तावित है।

4. आपत्ति संख्या–25 (आपत्तिकर्ता श्री राहूल कान्त माथुर) के संबंध में यह निर्णय लिया गया कि घड़ी चौराहा से श्यामनगर रोड़ का मार्गाधिकार मास्टर प्लान अनुरूप यथावत् रखा जाना प्रस्तावित है।

5. आपत्ति संख्या–32, 33, 34, 35, 36 एवं 38 (आपत्तिकर्ता श्री पृथ्वीराज एवं अन्य) के संबंध में यह निर्णय लिया गया कि पूर्व कमीटमेन्ट्स के मद्देनजर सड़क मार्गाधिकार के एलाईनमेन्ट में संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।

6. आपत्ति संख्या–40 एवं 41 (आपत्तिकर्ता श्री देवेन्द्रसिंह चौहान एवं अन्य) के संबंध में यह निर्णय लिया गया कि पावटा सी रोड का मार्गाधिकार मास्टर प्लान–2031 अनुसार रखा जाना प्रस्तावित है।

7. आपत्ति संख्या–45 (आपत्तिकर्ता श्री लक्ष्य) के संबंध में यह निर्णय लिया गया कि मास्टर प्लान–2031 में औद्योगिक इकाई अंकित है, मास्टर प्लान अनुसार आवासीय जोन एवं आसपास आवासीय गतिविधियों के मद्देनजर इस स्तर पर परिवर्तन किया जाना उचित नहीं है।

8. इसके अतिरिक्त नगर निगम, जोधपुर–दक्षिण द्वारा 4 अन्य सड़कों यथा 1– मोहनपुरा पुलिया से खासबाग, 2– खासबाग से भाटी चौराहा, 3– भाटी चौराहा से पांचबत्ती चौराहा एवं 4– रेलवे स्टेशन चौराहा से पुरी तिराहा तक सड़कों का मार्गाधिकार कम करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। चूंकि जोनल डवलपमेन्ट प्लान पर आपत्ति /सुझाव आमंत्रित किये जा चुके हैं। इन सड़कों के संबंध में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। अतः इन सड़कों का मार्गाधिकार जोनल प्लान प्रारूप के अनुरूप रखा जाना प्रस्तावित है।

इस प्रकार नगर निगम, जोधपुर दक्षिण के जोनल डवलपमेन्ट प्लान पर निर्णय लिया जाकर उक्त जोनल डवलपमेन्ट प्लान को अन्तिम रूप से स्वीकृत करने की अधिकारिता प्राधिकरण में निहित होने से बिन्दु संख्या 1 से 8 के प्रस्ताव अनुमोदन हेतु प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।''

अतः प्रकरण प्राधिकरण की बैठक के समक्ष अवलोकनार्थ एवम् विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा नगर निगम–दक्षिण, जोधपुर के जोनल डवलपमेन्ट प्लान को अन्तिम रूप दिये जाने के कम में जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 30 दिसम्बर, 2021 के कार्यवाही विवरण अनुसार प्रकरण में लिये गये निर्णय से प्राधिकरण को अवगत कराया गया। नगर निगम जोधपुर–दक्षिण के जोनल डवलपमेन्ट प्लान पर निर्णय लिया जाकर उक्त जोनल डवलपमेन्ट प्लान को अन्तिम रूप से स्वीकृत करने की अधिकारिता प्राधिकरण में निहित होने से कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 30 दिसम्बर, 2021 के एजेण्डा संख्या 4 में वर्णित

अनुसार बिन्दु संख्या 1 से 8 के प्रस्ताव अनुमोदन हेतु प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया था।

महापौर महोदया, नगर निगम–दक्षिण द्वारा एजेण्डा के बिन्दु संख्या–1 (रातानाडा से सर्किट हाउस तक सडक), बिन्दु संख्या–2 (पांचवी रोड से बाहरवीं रोड सडक), बिन्दु संख्या–4 (घडी चौराहा से श्याम नगर रोड) व बिन्दु संख्या–8 (1–मोहनपुरा पुलिया से खासबाग, 2–खास बाग से भाटी चौराहा, 3–भाटी चौराहा से पांचबत्ती चौराहा एवं 4–रेलवे स्टेशन चौराहा से पुरी तिराहा तक) के सडक मार्गाधिकार के संबंध में नगर निगम–दक्षिण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 22 दिसम्बर, 2021 में लिये गये निर्णय से भिन्नता होने बाबत अवगत कराया। जिस पर निर्णय लिया गया कि महापौर महोदया द्वारा अवगत कराये बिन्दु संख्या 1, 2, 4 व 8 में वर्णित सडकों के मार्गाधिकार का विस्तृत परीक्षण जोधपुर मास्टर प्लान–2031 रिपोर्ट के बिन्दु संख्या 5.8 का नोट–2 (पृष्ठ संख्या 129) के द्वारा गठित समिति से करवाकर कार्यकारी समिति के माध्यम से आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे एवं शेष बिन्दु संख्या 3, 5, 6 व 7 को यथावत् प्रस्ताव अनुसार अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया।

उक्त वर्णित अनुसार बिन्दु संख्या 1, 2, 4 व 8 में वर्णित सडकों को जोनल डवलपमेन्ट प्लान में विशेष सडक अंकित करते हुए नगर निगम, जोधपुर–दक्षिण के जोनल डवलपमेन्ट प्लान–2031 के प्रारूप को अन्तिम करने के संबंध में कार्यकारी समिति की अभिशंषा के दृष्टिगत जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2009 की धारा 23 के अन्तर्गत नगर निगम दक्षिण के प्रारूप जोनल डवलपमेन्ट प्लान को अन्तिम रूप दिया जाकर अधिसूचित करने का निर्णय लिया गया। मास्टर प्लान 2031 के सापेक्ष जोनल प्लान में किये गये डेविएशनस/विचलनों के संबंध में मास्टर प्लान–2031 में भी संशोधन/परिवर्तन का अंकन करते हुए इनका समावेश सुनिश्चित किये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 3 :: नगर निगम उत्तर के जोनल डवलपमेंट प्लान को अन्तिम रूप दिये जाने के संबंध में।

जोधपुर शहर के मास्टर डवलपमेंट प्लान 2031 क्षैत्र के जोनल डवलपमेंट प्लान बनाये जाने के क्रम में नगर निगम उत्तर, जोधपुर का जोनल डवपलमेंट प्लान प्रारूप तैयार किया जाकर इसके प्रारूप पर आमजन से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु दिनांक 19.11.2021 को अधिसूचना का प्रकाशन किया गया। जिसके क्रम में प्राप्त आपत्ति/सुझावों का विश्लेषण कर नगर निगम–उत्तर द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 के तहत गठित एम्पावर्ड समिति की बैठक दिनांक 24.12.2021 को आयोजित की गई। उक्त समिति की रिपोर्ट जरिये पत्रांक 12930 दिनांक 27.12.2021 को प्राधिकरण में प्राप्त हुई। नगर निगम उत्तर जोन के प्रारूप पर प्राप्त आपत्तियों के संबंध में नगर निगम उत्तर द्वारा तैयार रिपोर्ट पर विचार कर नगर निगम उत्तर जोन के जोनल डवपलमेंट प्लान को अंतिम रूप दिये जाने हेतु जोधपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्ताव संख्या 03 अवलोकनार्थ एवम् विचारार्थ रखा गया। जोधपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 30.12.2021 के कार्यवाही विवरण अनुसार प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

"बैठक में निदेशक–आयोजना ने इस संबंध में नगर निगम, जोधपुर–उत्तर द्वारा प्रस्तुत आपत्ति सुझावों के निसतारण संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत की। जो इस कार्यवाही का भाग परिशिष्ट–2 है। बैठक में प्रस्तुत आपत्ति/सुझाव पर विचार विमर्श कर निम्नलिखित आपत्तियों के संबंध में निर्णय लेते हुए शेष रिपोर्ट का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

1. आपत्ति संख्या–34 (आपत्तिकर्ता श्री फताराम पुत्र श्री अर्जुनराम भील) के संबंध में निर्णय लिया गया कि फायरिंग रेंज की मौका स्थिति अनुसार फायरिंग रेंज की सीमा दर्शायी जावे एवं फायरिंग रेंज की सीमा के साथ 100 फीट चौडी सडक दर्शायी जावे। आपत्ति में प्रस्तुत कमीटमेंट की 60 फीट चौडी सडक को उत्तर

दिशा की ओर विद्यमान सडक तक दिखाया जावे तथा उत्तर दिशा में स्थित सडक का मार्गाधिकार 60 फीट चौडा रखा जाकर जोनल डवलपमेन्ट प्लान में दर्शाया जाना प्रस्तावित है।

2. आपत्ति संख्या–40 (आपत्तिकर्ता एडवोकेट श्री जितेन्द्र कुमार गुर्जर) के संबंध में निर्णय लिया गया कि इस सडक को चौडी करने का कार्य प्रस्तावित है। अतः सूरसागर बाईपास से चांदपोल तक सडक का मार्गाधिकार 24 मीटर चौड़ा मास्टर प्लान/जोनल प्लान अनुसार ही रखा जाना प्रस्तावित है।

3. आपत्ति संख्या–42 (आपत्तिकर्ता श्री मदनसिंह राठौड़) के संबंध में निर्णय लिया गया कि जोनल डवलपमेन्ट प्लान में जलीय इकाई (वाटर बॉडी) का अंकन राजस्व मानचित्र के आधार पर दर्शाया जाना प्रस्तावित है।

4. आपत्ति संख्या–57 (आपत्तिकर्ता करणी डवलपमेन्ट एण्ड कन्स्ट्रक्सन) के संबंध में निर्णय लिया गया कि माचिया पार्क की सीमा का सही अंकन कर शेष भूमि का भू–उपयोग जोनल डवलपमेन्ट प्लान में समीपीय उपयोग अनुसार दर्शाया जाना प्रस्तावित है।

5. इसके अतिरिक्त नगर निगम, जोधपुर–उत्तर की एम्पावर्ड कमेटी द्वारा जोनल डवलपमेन्ट प्लान (प्रारूप) में प्रस्तावित चार निम्नलिखित विशेष सड़कों का मार्गाधिकार तय करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गयाः–

(1) आसूजी की प्याउ से अमृतलाल स्टेडियम होते हुए राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय तक
(2) मण्डोर पुलिस स्टेशन से गोकुलजी की प्याऊ होते हुए भाटी सर्कल से रामसागर सर्कल तक
(3) नागौरीगेट से महामंदिर चौराहे तक
(4) नागौरीगेट से राम मोहल्ला रोड से महात्मा फुलेराव पार्क तक

जिस पर बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि कम संख्या 1 व 2 में वर्णित सडक का मार्गाधिकार निर्धारित करने हेतु प्रकरण प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जावे एव कम संख्या 3 पर अंकित सड़क का मार्गाधिकार नगर निगम, जोधपुर–उत्तर के प्रस्तावानुसार 18 मीटर चौड़ा रखा जाना प्रस्तावित है। कम संख्या 4 पर अंकित सड़क का मार्गाधिकार मास्टर प्लान–2031 अनुसार 30 मीटर चौड़ा रखा जाना प्रस्तावित है।

इस प्रकार नगर निगम, जोधपुर–उत्तर के जोनल डवलपमेन्ट प्लान पर निर्णय लिया जाकर उक्त जोनल प्लान को अन्तिम रूप से स्वीकृत करने की अधिकारिता प्राधिकरण में निहित होने से बिन्दु संख्या 1 से 4 के प्रस्ताव अनुमोदन हेतु एवं बिन्दु संख्या 5 पर विचार विमर्श उपरान्त समुचित निर्णय लेने हेतु प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।''

अतः प्रकरण प्राधिकरण की बैठक के समक्ष अवलोकनार्थ एवम् विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा नगर निगम–उत्तर, जोधपुर के जोनल डवलपमेन्ट प्लान को अन्तिम रूप दिये जाने के कम में जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 30 दिसम्बर, 2021 के कार्यवाही विवरण अनुसार प्रकरण में लिये गये निर्णय से प्राधिकरण को अवगत कराया गया। नगर निगम जोधपुर–उत्तर के जोनल डवलपमेन्ट प्लान पर निर्णय लिया जाकर उक्त जोनल डवलपमेन्ट प्लान को अन्तिम रूप से स्वीकृत करने की अधिकारिता प्राधिकरण में निहित होने से कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 30 दिसम्बर, 2021 के एजेण्डा संख्या 3 में वर्णित अनुसार बिन्दु संख्या 1 से 5 के प्रस्ताव अनुमोदन हेतु प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया था।

प्रस्ताव के बिन्दु संख्या–5 में वर्णित 4 सडकें (यथा 1– आसूजी की प्याऊ से अमृत लाल स्टेडियम होते हुए राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय तक, 2– मण्डोर पुलिस स्टेशन से गोकुल जी की प्याऊ होते हुए

भाटी सर्कल से रामसागर सर्कल तक, 3– नागौरीगेट से महामंदिर चौराहे तक एवं 4– राम मौहल्ला रोड से महात्मा फुलेराव पार्क तक) के मार्गाधिकार निर्धारण बाबत विचार विमर्श किया गया। इसी दौरान बैठक में उपस्थित महापौर महोदया, नगर निगम, जोधपुर–उत्तर द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि 1–कृषि मण्डी चौराहा से किशोर बाग तक की मुख्य सडक का मार्गाधिकार 100 फीट रखे जाने, 2– सारण नगर आंगणवा होते हुए आठ मील मुख्य नागौर रोड का मार्गाधिकार 200 फीट के स्थान पर 100 फीट संशोधित किया जावे।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि बिन्दु संख्या –5 में वर्णित कम संख्या 1– यथा आसूजी की प्याऊ से अमृतलाल स्टेडियम होते हुए राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय तक एवं कम संख्या 2– मण्डोर पुलिस स्टेशन से गोकुल जी की प्याऊ होते हुए भाटी सर्कल से रामसागर सर्कल तक का मार्गाधिकार विभिन्न स्थानों पर अलग अलग होने से इन सडकों का मार्गाधिकार एवं बैठक में उपस्थित महापौर, नगर निगम–उत्तर द्वारा अवगत करायी गयी सडक 1–कृषि मण्डी चौराहा से किशोर बाग तक की मुख्य सडक एवं, 2– सारण नगर आंगणवा होते हुए आठ मील मुख्य नागौर रोड तक का मार्गाधिकार संबंधित प्रस्तुत प्रस्ताव का विस्तृत परीक्षण मास्टर प्लान रिपोर्ट के बिन्दु संख्या 5.8 का नोट–2 (पृष्ठ संख्या 129) के द्वारा गठित समिति से करवाकर कार्यकारी समिति के माध्यम से आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाने का निर्णय लिया गया एवं एजेण्डा के शेष बिन्दु 1 से 4 व बिन्दु संख्या 5 के कम संख्या 3 व 4 बाबत प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 30/12/2021 के प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

उक्त वर्णित अनुसार बिन्दु संख्या 5 के कम संख्या 1– यथा आसूजी की प्याऊ से अमृतलाल स्टेडियम होते हुए राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय तक एवं कम संख्या 2– मण्डोर पुलिस स्टेशन से गोकुल जी की प्याऊ होते हुए भाटी सर्कल से रामसागर सर्कल तक एवं (1) कृषि मण्डी चौराहा से किशोर बाग तक की मुख्य सडक, (2) सारण नगर आंगणवा होते हुए आठ मील मुख्य नागौर रोड तक सडकों को जोनल डवलपमेन्ट प्लान में विशेष सडक अंकित करते हुए नगर निगम, जोधपुर–उत्तर के जोनल डवलपमेन्ट प्लान–2031 के प्रारूप को अन्तिम करने के संबंध में कार्यकारी समिति की अभिशंषा के दृष्टिगत जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2009 की धारा 23 के अन्तर्गत नगर निगम उत्तर के प्रारूप जोनल डवलपमेन्ट प्लान को अन्तिम रूप दिया जाकर अधिसूचित करने का निर्णय लिया गया। मास्टर प्लान 2031 के सापेक्ष जोनल प्लान में किये गये डेविएशनस/विचलनों के संबंध में मास्टर प्लान–2031 में भी संशोधन/परिवर्तन का अंकन करते हुए इनका समावेश सुनिश्चित किये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 4 :: जोविप्रा में वर्तमान में प्रचलित शक्तियों के प्रत्यायोजन SOP को संशोधित कर प्राधिकरण बैठक मे अनुमोदन बाबत्।

क्रं सं.	प्रभारी अधिकारी एजेण्डा के सम्बन्ध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों व कार्यालय टिप्पणी अनुसार कोई तथ्य छुपाया नहीं गया है।	जोविप्रा में वर्तमान में प्रचलित शक्तियों के प्रत्यायोजन SOP को संशोधित कर प्राधिकरण बैठक मे अनुमोदन बाबत्।

जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर में वर्तमान में विकास कार्यो, सामग्री एवं सर्विस हेतु प्रचलित शक्तियों के प्रत्यायोजन (SOP) दिनांक 1 मई 2017 को लागू की गई थी इसके पश्चात् वित्त विभाग द्वारा संशोधन किये गये है। उन संशोधन का समावेश एवं व्यावहारिकता की दृष्टि से संशोधन की आवश्यकता है अतः वर्तमान शक्तियों के प्रत्यायोजन (SOP) में आवश्यक संशोधन जोधपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 25.10.21 के प्रस्ताव संख्या –13 द्वारा अनुमोदित है। कार्यकारी समिति का निर्णय निम्नानुसार है :–

" बैठक में विचार विमर्श के दौरान बैठक में उपस्थित निदेशक वित्त ने अवगत कराया कि प्रचलित (SOP) शक्तियों के प्रत्यायोजन में उपापन समिति में गठन में परिवर्तन प्रस्तावित कर स्वीकृतिकर्त्ता प्राधिकारी को अनुशंषा कमेटी से पृथक किया गया है। साथ ही कार्यकारी समिति की बैठक 06.02.19 एवं 07.03.19 में SOP के Item No - 26,27,29 (iii), 19 किये गये संशोधनो को प्रचलित SOP में समावेश किया गया। Goods & Services के Item की शक्तियों में A&F स्वीकृति, Bid स्वीकृति एवं Bid evaluation committe के गठन का प्रावधान किया गया है।"

"जोधपुर विकास प्राधिकरण में अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता के पद स्वीकृत होने पर संबंधित आइटमों में ACE को शक्तियों का भी समावेश किया गया है। Consultancy Services की शक्तियों में परिवर्तन, completion certificate जारी करना, Rate analysis एवं विशिष्ठियों का अनुमोदन करना, बजट प्रावधान का पुनर्नियोजन की शक्तियॉ, Single source Procurement Committee, spot purchase Committee का भी समावेश किया गया। जो आइटम work से संबंधित नहीं उन्हे Goods & Services शीर्षक में स्थानान्तरित किया जाना प्रस्तावित है।"

कार्यसमिति के अनुमोदन के पश्चात् SOP का अनुमोदन प्राधिकरण बैठक में रखा जाकर इसके अनुमोदन के पश्चात् राजपत्र में प्रकाशित करवाया प्रस्तावित है। अतः शक्तियो का प्रत्यायोजन (SOP) में संशोधन प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

Delegation of Powers to the Officers of Jodhpur Development Authority, Jodhpur

SOP Effective from 1st day of May 2017 (Revised on -----------------)

Part - I (Works)

General Note:-

1. Estimates should be framed at prevailing BSR.
2. Rate analysis of works shall be prepared by concerned Ex En. and counter signed by Director Eng. Before opening of price bid of the tender.
3. All powers, which are not specified in the schedule below, involving financial implication up to Rs. 500.00 Lacs, shall vest with JDC.
4. For delegation of powers which are not covered in this schedule of powers shall be *mutatis mutandis* applied as per PWF & AR and RTPPR 2013.
5. Bid amount means the amount offered by the Bid/contractor intended to be sanctioned.
6. Estimated amount means sanctioned estimated amount of item of BOQ schedule of work concerned.
7. Bid premium means percentage rate above/below quoted by the tenderer over BOQ Schedule amount.
8. A financial power or an authority, given under those rules, shall automatically vest in all higher authorities of that authority.
9. The financial power, not specifically delegated to any authority, shall vest with authority subject to RTPP Act & Rules.
10. No Administrative/Financial sanction shall be issued without appropriate budget provision. All sanctions shall be strictly restricted unto the limits of available Budget.
11. Wherever any specific power for a purpose has been given to an authority under this delegation, then it shall prevail over the general powers (if any) for that purpose.
12. The powers shall be subject to the budget provision in general and to the specific budget provisions, wherever mentioned in these delegations.
13. The powers contained in these delegations shall be subject to the rules and other provisions contained in the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012; Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013. **Time to Time Amendment in RTPP act & rule will be applicable as it is.**
14. Splitting of works for the purpose of keeping bids in its own competence by any officer is an irregularity. Therefore, splitting of bids should not be resorted to. If however, in genuine cases, it becomes necessary in the interest of work to split up, it should be done only after obtaining prior permission of the authority competent to sanction the bid of work without split up. The competent authority shall, while according permission mention the reasons for splitting of works.
15. The powers shall exercised only after comments/examination by the senior most Accounts Personnel (Director Finance/ Chief Accounts Officer/ Senior Accounts Office/ Accounts Officer/ Assistant Accounts Officer) Posted in the Office. While conveying sanction, the reference of

comments/examination by Accounts Personnel shall be mentioned. However, if the sanctioning authority differs with the advice of Accounts Personnel, the case must be submitted to next higher authority.

16. Wherever the words "bid amount" have been used in these powers, it means the amount offered by the bidder/ contractor which is intended to be sanctioned.
17. Wherever the words "estimated amount" are appearing, it means sanctioned estimated amount of items of G-Schedule or BOQ of the work concerned as the case may be.
18. "Bid premium" means percentage rate above/below quoted by the contractor over department rates or if worked out in item rates, the percentage of bid amount over sanctioned estimated amount for deciding competence to sanction bid.
19. Ensure that approved drawing & designs etc. are ready before NIB and land has been made over before sanction of Bid. Other actions required office level has been completed before sanction.
20. JDA shall prepare a procurement plan as per provision of Rule 7 of RTPP Rules, 2013.
21. Authority means the Jodhpur Development Authority constituted under section 3 of the Jodhpur Development Authority Act 2009.
22. **As on today post of A.C.E. does not exist in cadre strength. However the same has been included in SOP with a view to its creation in near future .**

ABBREVIATION	
EC : Executive Committee	GF & AR : General Financial & Accounts Rules
JDC : Jodhpur Development Commissioner	NIB : Notice Inviting Bid
DF : Director Finance	PPP : Public Private Partnership
DE : Director Engineering	PWF & AR : Public Works Financial & Accounts Rules
AE : Assistant Engineer	RTPP : Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules 2013
AMC : Annual Maintenance Contract	SE : Superintending Engineer
AS : Administrative Sanction	T&P : Tools & Plant
BOT : Build- Operate & Transfer	TS : Technical Sanction
BSR : Basic Schedule of Rates	FS : Financial Sanction
CAO : Chief Accounts Officer	PC : Procurement Committee
EE : Executive Engineer	ACE : Additional Chief Engineer
ACE: Additional Chief Engineer	

S.NO	Nature of Power	To whom delegated	Power	Remark
1	2	3	4	5

S.NO	Nature of Power	To whom delegated	Power	Remark
ADMINISTRATIVE AND FINANCIAL SANCTIONS				
1	Administrative & Financial approval to execute a Project/Scheme/Works in whole or part including repairs and maintenance.	EC	FULL POWERS	Unless restricted by State Govt
		JDC	Up to Rs. 5.00 Crore	On recommendation Public works committee If Amt. is 50 lac & above
2	Revised Administrative & Financial approval to execute a Project/Scheme/ Works in whole or part including repairs and maintenance.	E.C. (Inclusive of Revised A&Fs)	Above Rs. 5.00 Crore Up to 50% of original value of the Contract	Note- (i) Revised estimate must be sanctioned by competent authority before the proposal for revised A&F (ii) As per RTPP Rule-73**(3)(iii)**
		JDC (Inclusive of Revised A&Fs)	Up to Rs. 5.00 Crore up to 50% of original value of the Contract	
3	Splitting of A & F Sanctions.	DE	Full power	(With Recommended of Bid Sanction Authority of work without split up) (see general note 14)
4	To permit undertaking contribution/ deposit works and to accept contribution/ deposit in respect of them.	EC	Full Power	These powers shall be exercised subject to following conditions: - Note: - 1. Deposits may be accepted in lump sum or in installments on prescribed dates as mutually agreed after ensuring that full amount is provided for in the budget of the concerned organisation and installments would be paid on specified dates. 2. Deposit works involving share of JDA will be agreed/ sanctioned only with the concurrence of EC. Revised cost will also be bome in the same proportion as decided
		JDC	Up to Rs. 1000.00 Lacs	
		DE	Up to Rs. 300.00 Lacs	
		ACE	Upto Rs 250.00 Lacs	
		SE	Up to Rs. 150.00 Lacs	
		EE	Up to Rs. 30.00 Lacs	

S.NO	Nature of Power	To whom delegated	Power	Remark
				by EC. 3. Expenditure will be charged against and limited to the deposit received only, in no case it should exceed the deposit. 4. Percentage charges, as approved from time to time, shall be levied as decided in byelaws/administrative orders.
	TECHINICAL SANCTIONS			
5	To accord technical sanction to detailed original/revised or supplementary estimated based on A&F sanction already available for orginal work, deposit works contribution works subject to the condition that revised A&F shall be sought in Advance, If the revised as supplementing estimate exceed the orginal A&F sanction by more than 10%	DE	Full Power	These powers shall be exercised subject to following conditions only: - Note: - 1. There is provision in the administrative approval to cover the particular type of work and sanction of the detailed estimates does not result in excess of more than 10% over the provision under the particular sub-head of the administratively approved project estimate under which the estimate is sanctioned but it shall not exceed the administrative approval of the project as a whole. 2. Revised estimate involving excess of more than 10% over original sanctioned estimate shall be submitted to the next
		ACE	Upto Rs 250.00 Lacs	
		SE	Up to Rs. 150.00 Lacs	
		EE	Up to Rs. 50.00 Lacs	

S.NO	Nature of Power	To whom delegated	Power	Remark
				higher authority for technical sanction after obtaining revised AS/FS from Competent Authority. Incase of CE is next highter authority will be CE himself (CE means Chief Engineer) 3. If the cost of the work, according to the revised estimates, exceeds the limits of the powers to accord technical sanction, the revised estimate should be submitted to the next higher authority. In CE next hight authority will be CE himself. 4. Revised Administrative & Financial approval is obtained if revised cost is more than 10% of original cost. PWF&AR-286&287 5. For supplementary estimate, the authority who sanctioned original estimate will be competent provided original plus supplementary is in his competence. 6. No officer is competent to pass any excess over a revised estimate sanctioned by an authority higher than himself. 7. For subsequent revision of estimate also, the amount of estimates shall form basis for

S.NO	Nature of Power	To whom delegated	Power	Remark
				revision. 8. Rates of Non BSR items shall however be approved by the DE only.
6	To accord administrative and technical approval/Terms of Reference's approval of a consultant and to approve bids for conducting of detailed surveys and investigation, preparation of designs and drawings, project formulation and preparation and other studies, appointing consultant, hiring of consultancy services etc., other than by department agency e.g. private consultancy services.	EC	Full Power up to **2%** of the project cost.	Note: - 1. A certificate is to be recorded by the Approving Authority that the departmental organisation existing for the work is either fully occupied or is not well equipped for the job. 2. Procurement is made as per & RTPP Act/Rules. (PWF&AR-306A) 3. Retired personnel will not be eligible for such assignments for two years after retirement, except with specific Government sanction. 4. There should be specific budget provision for this purpose.
		JDC	Up to Rs. **50.00** Lacs or **2%** of the project cost whichever is less.	
		DE	Up to Rs. **15.00** Lacs or **2%** of the project cost whichever is less.	
7	To accept bids for works on Build, operate and Transfer (BOT) basis, PPP Projects including acceptance of bids for consultancy of these projects.	EC	Full Power	Guidelines set by state government should be followed
8	In emergent conditions like flood relief and other natural calamities, the subject matter of procurement may be procured upto the ceiling rates fixed by district level committee. Constituted under RTPPR-	EC	Up to Rs. 100.00 Lacs	Note 1. Procurement shall be done as per RTPP Act & rules 2. Ceiling rates should be as approved by committee constituted under Rule 17(3) of RTPP Rules.
		JDC	Up to Rs. 50.00 Lacs	

S.NO	Nature of Power	To whom delegated	Power	Remark
	17(3)			
9	To engage labour through service contractor in emergent conditions.	DE	Up to Rs. 5.00 Lacs	Note: - 1. As per the provisions of RTPP Act & Rules. 2. For Exceptionally emergent cases only like flood, Fire, earth quake, cyclones, lands sliding, breach of canals, pipe lines & roads with prior approval of JDC. Such labour shall not be employed on regular duties of a department such as office peons/ orderlies/ chowkidars etc. 3. The rate of daily wages shall not exceed 20% of the minimum wages of the area concerned, otherwise approval of the next higher authority will necessarily be obtained. 4. Work done by such labour shall be entered in M.B., Wherever susceptible of measurement, besides, attendance register, otherwise, a certificate by EE shall be recorded of work being unsusceptible of measurements.
		ACE	Upto Rs 3.50 Lacs	
		SE	Up to Rs. 2.50 Lacs	
		EE	Up to Rs. 1.00 Lac	
10	To rescind contracts, where such cancellation does not result in any loss to the JDA.	EC/JDC/DE/SE	Full Power	1. Full power to the limit of his power to acceptances of contracts.

S.NO	Nature of Power	To whom delegated	Power	Remark
				2. Certificate of no loss should be recorded by Bid sanctioning Authority
11	To communicate and implement the decision of the standing committee constituted for settlement of disputes under "Condition of Contract"	JDC	Full Power	Note :- Standing Committee comprising of the followings would decide the matter within 60 days. JDC DL DE DF Sec. SE Concern (Member Secretary)
12	To divert savings out of provision for contingencies to meet cost of any new work or repair, not provided for in the estimate, provided such diversion does not materially alter the design provided in the original estimates sanctioned by a higher authority and is in respect of the work fairly contingent upon the work itself.	EC	Full Power	
13	To transfer ascertained savings from any one portion of the project to another, within the sanctioned estimate,	JDC	Full Power	Note 1. Procurement shall be done as per RTPP Act & rules 2. Ceiling rates should be as approved by committee constituted under Rule 17(3) of RTPP Rules.
14	To permit deposit with other Govt. Deptts. Such as PHED, JVVNL, Municipalities or any other Deptts/ Board subject to administrative, financial approval of project being available.	JDC	Full Power	With consultation with DF These powers shall be exercised subject to following conditions: - Note: - 1. Deposits may be accepted in lump sum or in installments on prescribed dates as

S.NO	Nature of Power	To whom delegated	Power	Remark
				mutually agreed after ensuring that full amount is provided for in the budget of the concerned organisation and installments would be paid on specified dates. 2. Deposit works involving share of JDA will be agreed/ sanctioned only with the concurrence of EC. Revised cost will also be bome in the same proportion as decided by EC. 3. Expenditure will be charged against and limited to the deposit received only, in no case it should exceed the deposit. 4. Percentage charges, as approved from time to time, shall be levied unless exempted by F.D.
15	To issue notice for inviting Bid and advertise through DPIR/Samwad cell.	EE	Full Power	Note: - 1. Short term NIB should be approved /permitted by competent authority. 2. Provided A&FS and TS is available already
16	To grant permission to float short term bid	JDC	Full Power	As per RTPP rule 43(7)
17	To accept/Reject bids for the execution of sanctioned work or part of sanctioned work and for rate contracts (area) wise for	JDC	Above Rs. 500.00 Lacs	On recommendation of PC comprising of DE, DF & Secretary.

S.NO	Nature of Power	To whom delegated	Power	Remark
	repairs, maintenance and petty work, supply of material for these works.	DE	Up to Rs. 500.00 Lacs	On recommendation of PC comprising of ACE,SE,CAO & EE.
		ACE	Upto Rs 250.00 Lacs	On recommendation of PC comprising of SE, CAO& EE.
		SE	Up to Rs. 150.00 Lacs	On recommendation of PC comprising of C.A.O. & EE, AEN
		EE	Rs. 50.00 Lacs	On recommendation of PC comprising of AO/AAO, AEN & JEN

These powers shall be exercised subject to following conditions :

Note: -

1. The amount shown above are Bid amount quoted by the contractor which is intended to be sanctioned.
2. Bids will be invited & processed strictly as per the provisions of R.T.T.P. Act & Rules. Conditions (General/Special) of the bid documents shall not go against the provisions of RTPP Act & Rules.
3. These powers are subject to condition that the contractor's Bid amount do not exceed the amount of G-Schedule/Bill of Quantities/Activity Schedule (as per sanctioned estimates amount) by more than 10% and also that the overall monetary limits of financial powers mentioned above against each authority are not exceeded.
4. Thus both the conditions should be satisfied (i) that contractor's Bid amount must be within limits prescribed above and (ii) Bid premium/ percentage of contractor's Bid amount over sanctioned estimate amount of G-Schedule is upto 10%.
5. If the Bid amount of the contractor exceeds the estimated amount of the work by more than 10% the powers will be exercised by the next higher authority. Where 'G' Schedule is based on a pervious year's BSR and Bid received when evaluated to the current BSR, applicable on the date of opening of Bid do not show any increase over the such evaluated estimated amount and Bid amount is within financial limits to sanction Bid as indicated each, the Bid need not be referred to nest higher authority provided the revised estimates has been prepared and submitted to competent authority to sanction and copy of the revised estimate have been enclosed with the Bid. Mere revision of BSR do not qualify to use this provision.

S.NO	Nature of Power	To whom delegated	Power	Remark
		6. If only single qualified/ responsive bid is received in response to a NIB, Same procument committee will be competent to sanction as per the provision of RTPP Act & Rules. (Rule 68) **(2) (3) (Amended wide Letter & date 06-08-2018)** 7. These powers will be exercised only after examination and written comments of the concen Accounts Personnel as laid down in general conditions of these powers. 8. Rates of Non-BSR items shall however be approved by the DE before inviting bids. 9. Bid sancting authority/Higher authority & appellant Authority can reject the bid.		
17 A	Opening of Bid of single envelop system	Committee comprising of Ex. En. A.En. & A.O./A.A.O.	Full Power	- Subject to fulfill condition of PWF&AR & RTPP Act & rules **- Formation of the committee's under rule 03 of RTPP**
17 B	Opening of two/three bid system	Committee comprising of Ex. En. A.En. & A.O./A.A.O.	Full Power	
17 C	Technical Evaluation of two/three bid system	Committee comprising of ACE/S.E. CAO & Ex. En.	Full Power	
18	To undertake negotiations	JDC	Above Rs. 500.00 Lacs	Note:- The process shall be strictly undertaken according to rule 69 of RTPPR 2013.
		DE	Up to Rs. 500.00 Lacs	
		ACE	Upto Rs 250.00 Lacs	
		SE	Up to Rs. 150.00 Lacs	
		EE	Rs. 50.00 Lacs	
19	Bids have to finalized within mentioned period, after this period **same** authority shall exercise the power **with recoreded reasons.**	JDC	50 days	Time frame prescribed in rule 40(2) of RTPP Rule 2013 shall be strictly followed. Also Read with RTPP rule 70 (2),48(1)(2)(3) & Amendmend of 06-08-2018 in rule 40(2)
		DE	45 days	
		ACE	35 days	
		SE	30 days	
		EE	20 days	
20	To withdraw work from the contractor under relevant clause of agreement, for recorded reason provided such withdrawal	JDC	Above Rs. 500.00 Lacs	Note:- 1. Powers shall be exercised with concurrence of
		DE	Up to Rs. 500.00 Lacs	
		ACE	Upto Rs 250.00 Lacs	

S.NO	Nature of Power	To whom delegated	Power	Remark
	does not result into an unauthorised aid to contractor.	SE	Up to Rs. 150.00 Lacs	corresponding PC.
		EE	Rs. 50.00 Lacs	
21	To sanction running rate contract for works to be executed under piece work agreement, after calling division wise bids for the specific purpose.	DE	Full Power	As per rule 27 of RTPPR
22	To issue work order/permission to issue work order for original or repairs work up to the sanctioned estimated rates based on BSR when no tender are received. (Work order system)	EE	Up to Rs. 2.00 Lac on each occasion **subject to Annual limit of Rs. 5.00 Lacs.**	Note:- (1). Subject to overall limit of Rs. 10.00 lacs during a financial year for each zone/division. (2). As per RTPP Rule 2013 (Rule 27) & Rule 323 of PWF&AR
23	To Approve basic schedule of rates (BSR)	DE	Full power	Note: - 1. These powers will be exercised by the DE only on the detailed recommendation of a Task Force in which DF will invariably be member. The Task Force will standardize various analysis of rates of components and determine rates on the basis of data/rates furnished by the SE/Zone level officers or other works departments 2. BSR should be revised annually. Timely action shall be initiated so that the new BSR be made effective from the start of new financial year. 3. Those Non-BSR items which are of regular use for the

S.NO	Nature of Power	To whom delegated	Power	Remark
				department must be brought into the list of BSR items regularly.
24	To enlist contractor for various type of works as per Enlistment Rules of the Authority.	JDC - AA class **- E-xy-I class** DE - A,B class **- E-xy-II class** SE - C,D class **- E-xy-III, IV class**	The performance of the contractor shall be reviewed at the end of each financial year. On receipt of confidential report from the officers under whom he has worked in the last financial year for quality of works, ability to complete the work in the stipulated time, financial capacity and behavior towards officers and staff of the authority as well as other relevant yard stick fixed by the Authority.	Enlistment will be done as per PWF&AR until enlistment rules of Authority are made. Concerning matter should be routed through Director Finance for AA Class Contractors, CAO for A, B Class Contractors and AO/AAO for C, D Class Contractors.
25	To sanction execution and payment for extra items (BSR+Non BSR) as per Bidding documents/conditions of contract.	Bid Sanctioning Authority	Upto 5% of the of original Contract value as per RTPP Rule 73(2) **order date 16-02-2018**	These powers shall be exercised subject to the following: - Note: - 1. Total amount of the work

S.NO	Nature of Power	To whom delegated	Power	Remark
				including additional quantities and extra items (BSR+Non BSR) shall not exceed the administrative and financial sanction for the work. 2. Total amount of work i.e. tendered amount plus cost of additional quantities and extra items (BSR+Non BSR) do not exceed monetary limit to accept bid. If the total amount (including additional and extra items (BSR+Non BSR) exceeds the monetary limit to accept bid, the matter shall be referred to next higher authority. 3. The extra items should be part and parcel of the work under execution and should be fairly contingent to it and therefore the execution of items of works of different nature or execution of items or work of similar nature of another reach/ site shall not be treated as extra item. 4. Total cost of all extra items shall not exceed the limits specified above. 5. Revised estimate have been got approved from the competent authority if he items are not provided for in original

S.NO	Nature of Power	To whom delegated	Power	Remark
				estimates. 6. Scale of accommodation or norms, types, designs sanctioned by higher authority are not exceeded. 7. Material deviations from designs and scope of the Project will require approval of the original authority. 8. The rates of Non-BSR items shall be got approved from the DE before sanction of extra items. 9. The fair market value of such Extra Item payable by the procuring Entity to the contractor shall be determined by DE
26	To sanction execution and payment of additional quantities of items existing in schedule-G or bill of quantities (BOQ) of a particular work. (Excess)	JDC	Up to 50% of the original contract amount.	These powers shall be exercised subject to the following conditions: - Note: - 1. Total amount of work including additional quantities & extra items (BSR+Non BSR) shall not exceed 50% of the value of original contract in any case as per provision of RTPP Rule 73 (3). 2. Total amount of the work including additional quantities and extra items (BSR+Non BSR) should not exceed the administrative and financial
		DE	Up to **25%** of the original contract amount.	
		ACE	Up to **10%** of the original contract amount.	
		SE	Up to **8%** of the original contract amount.	
		EE	Up to **5%** of the original contract amount.	

S.NO	Nature of Power	To whom delegated	Power	Remark
				sanction for the work. 3. Total amount of work i.e. tendered amount plus cost of additional quantities and extra items (BSR+Non BSR) shall not exceed the monetary limit to accept bid. If the total amount (including additional and extra items (BSR+Non BSR)) exceed the monetary limit to accept bid, the matter shall be referred to next higher authority. 4. The additional quantities should be part and parcel of the work under execution and therefore even the execution of works of different nature or execution of quantities/work of similar nature of another reach/site shall not be treated as additional quantity. 5. Revised estimates, if required, have been approved by the competent authority. 6. Provided that in exceptional circumstances and without changing the scope of work envisaged under the contract, a procuring entity may procure additional quantities beyond 50% of the quantity of the individual items as provided in the original work order with

S.NO	Nature of Power	To whom delegated	Power	Remark
				prior approval of the Executive committee concerned as follow :- (i) the procuring entity shall obtain prior approval for revised requirements from the competent authority for reasons to be, recorded in writing. Wherever necessary, due to the quantities, the procuring entity shall obtain prior and revised technical, financial and administrative sanctions from the competent authorities. (ii) that the additional quantities so procured shall be part and parcel of the work being executed. (iii) that the limit of 50% of the value of original contract shall not be exceeded in any case. 7. order for additional quantity may be placed, if allowed in bidding documents/contract and the original order was given after inviting open competitive bids.
27	To grant provisional time extension to the agreements, to keep the agreement alive.	EE	Full power, with recorded reasons	1. Written application for the same may produce by contractor/As per requirement of JODA

S.NO	Nature of Power	To whom delegated	Power	Remark
28	To grant for recorded reasons, final extension of time for the execution of works or supply of materials or other performances of the contract. & to lavy final liquidates damages in cases of delay.			Note: - 1. For reachwise / spanwise interim time extension in case, time spans/ reaches have been prescribed in the agreement for prorata progress, the bid sanctioning authority shall have full powers as per provisions of rules. 2. In case, extension of time involves payment of price escalation approval of EC shall be obtained. 3. Hindrance Register shall be maintained by Engineer incharge and reasons for delay (on account of department/ contractor) shall be specifically recorded eventwise with full details. Every extension case must accompany copy of Hindrance Register and the record of corrective measures taken by Engineer incharge. 4. When JDC in procuring committee the power of 28 (II) & (III) will be vest in E.C. 5. When EC itself procuring committee the power of 28 (II) & (III) will be also vest in E.C.
	(i) For a final extension of time which results in slippage upto 1.5 times of the stipulated work order duration.	Bid Sanctioning Authority	Full Power as per "Condition of Contract" provided it does not involve payment of price escalation.	
	(ii) For a final extension of time which results in slippage upto two times of the stipulated work order duration.	Next higher Authority of the Bid Sanctioning Authority	Full Power as per "Condition of Contract" provided it does not involve payment of price escalation.	
	(iii) For a final extension of time which results in slippage more than two times of the stipulated work order duration.	JDC	Full Power as per "Condition of Contract" provided it does not involve payment of price escalation.	
29	To sanction repayment of Security Deposits/Performance Security including PG from contractor on satisfactory completion of original and repair works	EE	Full power	**After issue Completion Certificate by concern XEN &** that defects pointed out by any higher/authority/other have been

S.NO	Nature of Power	To whom delegated	Power	Remark
	after the lapse of the period, as specified in the contract.			removed by contractor
30	To execute the instruments relating to acceptance of bids on behalf the JDC.	EE	Full power	
31	To accept bonds of auctioneers & security bonds for the due performance and completion of work.	EE	Full power	
32	To remit or reduce or revise for recorded reasons the amount of compensation provided in the agreement.	EC	Full power	With consultation of DF
		JDC	Up to Rs. 50 lacs	
33	To Procure through single source method **under rule 17 of RTPP**	JDC	FULL POWER	On recommendation of PC comprising of DE, DF & Secretary.
		Secretary	Up to Rs. 8.00 Lacs	On recommendation of PC comprising of DE, DF & SE.
		DE	Up to Rs. 5.00 Lacs	On recommendation of PC comprising of CAO, SE, XEN
34	To Procure through spot purchage method **under rule 25 of RTPP**	Secretary	FULL POWER	spot purchage committee comprising AO/AAO, XEN, AEN Concern
35	To Analysis the rate & approval of technical specification	DE	FULL POWER	On recommendation & Justification of PC comprising of SE, XEN
36	To approve Public private participation projects such as B.O.T./Swiss challenge method.	EC	Full Power	In accordance with RTPP Rules 79(A).

S.NO	Nature of Power	To whom delegated	Power	Remark
37	To sanction payment of price variation under clauses of agreement. (Under clause-45 of agreement)	Original Bid Sanction Authority	Full Power (For the work done within original stipulated completion period of work)	Note :- 1. For work done beyond stipulated original period of completion of the work or a portion of work or a portion of (Reach), the payment of escalation will be made after sanction of final extension in completion period by the competent authority. 2. The escalation will be granted as per conditions laid down in the agreement in relevant clauses. 3. No escalation will be granted on the basis of provisional price indices or provisional time extension. **4. Negative Price Variation (If any) Shall also be Calculate before find payment as per PWF&AR Provision.**
38	Physical verification of works and inspection for Quality control measures	DE	Full Power	Assisted by ACE/SE
		ACE	Upto Rs 250.00 Lacs	Assisted by SE
		SE	Up to Rs. 150.00 Lacs	Assisted by EE
		EE	Up to Rs. 50.00 Lacs	Note 1.Agreement Amount is more than 25 Lacs than I & final, III, V and every Alternate Bill will be produced to ACE/DE for approval before the Payment.

S.NO	Nature of Power	To whom delegated	Power	Remark
39	Third party inspection regarding Quality Control	DE	Full Power	Note 1. This clause shall be applicable to all type of works involving outlay of Rs. 50.00 lac or more. 2. Selection of third party & payment thereof will depend on the nature of work which shall be discretionary on the part of DE with concurrence of DF. 3. ConcerningExecutive Engineer shall be responsible for carrying out inspection.
40	Component of sanction estimate for clause 45 of agreement must be approved by	DE		The components of sanction estimate for price escalation purpose are to be got sanctioned from DE. It is mandatory for EE concern to ensure that component decided are correct & has been examined by accounts person of corresponding PC.
41	To issue work Experience Certificate/ completion certificate	DE	Above Rs 300.00 Lacs	The Technical officer will issue completion certificate after completion of work.
		ACE	Upto Rs 250.00 Lacs	
		SE	Upto Rs 200.00 Lacs	
		XEN	Upto Rs 50.00 Lacs	
42	Budget Re appropriation	Authority	FULL POWER	On recommendation of JDC, DF, DE

Part - II (Goods & Services)

S.NO	Nature of Power	To whom delegated	Power	Remark
1	2	3	4	5
ADMINISTRATIVE AND FINANCIAL SANCTIONS				
1	To accord Administrative & financial approval for Goods & Services	EC	Above 100 lacs	Note:- 1. Demand for such purchase will be determined by OIC Concern/Xen HQ/AEN HQ 2. Justification of demand for the same will be made by OIC of concern zone
		JDC	Upto Rs 100.00 lac	
		SEC.	Upto Rs 25.00 lac	
2	To accept/Reject bids for for Goods & servies	EC	Above 100 lacs	1. On the recommendation of PC Comprising JDC, DF,DE,Sec.
		JDC	Upto Rs 100.00 lacs	2. On the recommendation of PC Comprising DF,DE,Sec, Xen, HQ/ OIC Concern, Zone
		SEC.	Upto Rs 25.00 lac	3. On the recommendation of PC Comprising CAO Xen, HQ, AENHQ/ OIC Concern, Zone
3	To approve bidding document for good & services	JDC	Above 75.00 lacs	1. On recommendation of PC comprising of DF, DE, ACE, Secretary.
		SEC.	**Upto** 75.00 lacs	2. On recommendation of PC comprising of DE, CAO, SE, XEN.
		DE	Upto Rs 50.00 lac	3. On recommendation of PC comprising of ACE, CAO, SE, XEN .
		ACE	Upto Rs 25.00 lac	4. On recommendation of PC comprising of SE, CAO, XEN ,AEN
				Note- 1) PC will prepare bidding document with the discussion with expert

S.NO	Nature of Power	To whom delegated	Power	Remark
				2) All the relevant rules, terms & conditions will incorporate which are according to policy of govt of Raj notification of FD, GF&AR RTPP Act & Rules 3) Bidding document will be finalised after consult with the committee **here by** for the procument according to the policy of GOR for the promotion of SMME
4	To levy final liquidated damages in cases of delay in supplies of goods & services.			
	(i) In cases where actual work completion duration has been upto 1.5 times of original stipulated work order duration.	Bid sanctioning Authority	Full Power	Note: - These powers are not applicable for interim liquidated damages.
	(ii) In cases where actual work completion duration has been upto two times of original stipulated work order duration.	Next higher Authority of bid sanctioning Authority	Full Power	
	(iii) In cases where actual work completion duration has been more than two times of original stipulated work order duration.	JDC	Full Power	
S.NO	**Nature of Power**	**To whom delegated**	**Power**	**Remark**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
5	To sanction advance for purchase of store (i) In case of R/C	DE	Up to 98% of the cost of goods	Subject to approval of JDC
			Up to 90% of the cost of goods worth Rs. Three Lacs.	
			Note a) Advance for purchase of stores may be given in exceptional circumstances taking necessary precaution for securing the	

S.NO	Nature of Power	To whom delegated	Power	Remark
			financial interest of JDA. b) Such advance should be made on submission of Railway or Road Transport Receipts. The balance should be paid on receipts of the goods subject to the usual verification. c) The advances payment should preferably by made on receipt of a certificate of personal inspection of goods by the consignee who may employ an officer not below the rank of an Assistant Engineer. d)) It should also be made clear to the suppliers that they are in no way absolved from the responsibility in respect of quality and quantity of stores dispatched by them and recoveries are liable to be made if the stores received are found in way to be defective or short in quantity. e) Inspection before dispatch of good/article shall be ensured where the advance payment amount 75% of the order placed and exceed Rs. 50000/-	
6	To sanction purchase of spare parts of a particular make for machine from the manufacturer or original equipments supplier of from the sole distributors.	DE	Up to Rs. 2.00 Lacs (beyond this limit tender should be invited)	Note 1. Prior A&FS from JDC will be mandatory. 2. As per procedure laid down in RTPPR-32 and relevant notification dated 04.09.2013.
7	To Purchase of spare parts after inviting limited tenders of a particular machine from the firms approved by the JDC in case where the material is not supplied with in the delivery period by the rate contractor.	Dir. Engg.	Up to Rs. 1.00 Lacs in each case	
		EE	Up to Rs. 0.25 Lacs in each case with annual limit ofRs. 1.00 Lacs	
8	To sanction purchase of spare parts in emergent cases, without inviting tenders.	EE	Up to Rs. 0.50 Lacs. (maximum annual limit- Rs. 2.00 Lacs)	
9	To pass indents on other department articles required for sanctioned works.	EE	Full power	
10	To sanction the limits of Reserve stocks of divisions	JDC	Full power	
11	To sanction estimates for repair and carriage	DE	Full power	

S.NO	Nature of Power	To whom delegated	Power	Remark
	of tools and plants subject to specific A&F.	SE	Up to Rs. 1.00 Lacs	
		EE	Up to Rs. 0.50 Lacs	
12	To accept bids for the sale of tools and plants declared surplus by the competent authority in accordance with rules.	JDC	Full power	As per procedure laid down in rule 16 to 27 of GF&AR vol I part II.
		DE	Up to Rs. 150.00 Lacs	
		ACE	Up to Rs. 50.00 Lacs	
		SE	Up to Rs. 25.00 Lacs	
		EE	Up to Rs. 5.00 Lacs	
13	To issue stock or other materials to works at stock or market rates whichever is greater when their issue is not provided for in the contract.	EE	Full power subject to the condition that a report should be made to DE and DF stating the amount of the issue and the circumstances require it.	
14	To declare any stores (including tools & plants stocks and materials received from work dismantled) as surplus or unserviceable and sanction their sale by public auction or destruction.	DE	Full power	Note: - 1. These monetary limits refer to original purchase price which may be estimated if original price is not known. 2. Relevant provisions of GF&AR shall be *mutatis mutandis* adhered to.
		EE	Up to Rs. 0.50 Lacs.	
			Note: A report should be made to the Director (Finance). Detailed survey report shall be prepared and verified by committee.	
15	To sanction rate for hiring of departmental tool & plans	DE	Full power subject to rules	With prior concurrence from JDC
16	To sanction rate for hiring of departmental tool & plants and other materials obtained for external sources.	EE	Full power for each type of machine Rs. 10000/- only in emergent case after recording reasons.	With prior concurrence from JDC
17	To approve and counter sign indents for instruments mathematical instruments, office calculator etc.	DE	Full power	
		EE	Full power if within the scale sanctioned for the division.	
18	To sanction after due investigation the write off value of all type of stores, and plant lost destroyed or damaged by accident,	JDC	Full power	As per GF&AR Volume I part II Rule 20
		DE	Up to Rs. 3.00 Lacs in each case	

S.NO	Nature of Power	To whom delegated	Power	Remark
	negligence, and fraud or otherwise.	ACE	Up to Rs. 2.00 Lacs in each case	
		SE	Up to Rs.1.00 lacs in each case	
		EE	Up to Rs.5,000/- each case	
19	To sanction the write off tool and plants which have become unserviceable after fair wear and tear.	DE	Full power	Subject to GF&AR Volume I part II Rule 17,18
20	To sanction after due investigation the write off of measurement books muster role which have been lost.	DE	Full Power	Note: 1. In each case while ordering write off the DE should pass a separate order after due Investigation & compliance of rules giving full details. Copy of the order should be endorsed to Director.(Finance) and JDC. 2. FIR must be done
21	To sanction estimates for losses on stock due to depreciation owing to a fall in prices or any cause or adjustment of losses on manufacturers accounts.	JDC	Full Power	
		DE	Up to Rs.0.50 lacs	
		SE	Up to Rs .20 lacs	
22	To write off discrepancies in accounts	EE	Up to Rs.50/-	
23	To Write off Infractuous expenditure on construction.	DE	1% of the contract value subject to a ceiling of Rs.50,000/- in consultation with Director(Fin.)	
24	To sanction compensation for the lands and crops standing on the land taken over by the authority for public works by negotiations provided amount is certified by land acquisition are reasonable and not excessive.	JDC	Full Power	
		DE	Rs. 5.00 lace	
		EE	Up to Rs. 0.50 lacs. For each case.	
25	To sanction compensation, under the	JDC	Full Power	Note: -

S.NO	Nature of Power	To whom delegated	Power	Remark
	workmen's compensation Act of under any other law for the time being of in force on as prescribed under the rules.	DE	Up to Rs.2.00 lacs	If the award is pending for sanction before Competent authority. Director Engineering and SE may sanction an advance payment up to 75% of the compensation payable.
		ACE	Up to Rs.1.50 lacs	
		SE	Up to Rs.1.00 lacs	
		EE	Up to Rs.0.50 lacs	

Note -

1. This Schedule of Powers shall come in to force from 1st day of May 2017 & amended on...................... upon all work orders and agreements which are live and ongoing on that day.
2. Any matter not covered in this Schedule of Powers shall be exercised as per RTPP Act 2012&Rules 2013.

Any change in RTPP act-2012, Rule 2013, PWF&AR & GF&AR will supercede on this SOP.

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का विस्तृत परीक्षण कर आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 5 :: वित्तीय वर्ष 2021–22 में बजट पुनर्विनियोजन को प्राधिकरण बैठक मे अनुमोदन बाबत्।

क्रं सं.	प्रभारी अधिकारी एजेण्डा के सम्बन्ध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार एजेण्डा में किसी प्रकार का तथ्य छुपाया नहीं गया है।	बजट अनुमान वित्तीय वर्ष 2021–22 मे बजट प्रावधान से पुनर्विनियोजन किया जाना प्रस्तावित है।

वित्तीय वर्ष 2021–22 मे बजट पुनर्विनियोजन का प्राधिकरण बैठक मे अनुमोदन बाबत् रखा जाना है जिसको पत्रावली में अध्यक्ष जो.वि.प्रा. द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है साथ ही नवीन मद हेतु नये बजट लेखाशीर्षक भी खोलने के प्रस्ताव भी अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। अतः जिन कार्यो हेतु बजट पुनर्विनियोजन करवाया गया है, उनके प्रस्ताव निम्नानुसार हैं:–

क्रं. सं.	कार्य का नाम	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (लाखो में)
.	Renovation of Existing building of Jai Narayan Vyas Town Hall, Jodhpur, including all addition & Alteration in civil work, Electric work, modification of all toilets, complete auditorium interior work etc.	1150.00

उक्त कार्य हेतु बजट अनुमान 2021–22 मे पुनर्विनियोजन के प्रस्तावों को प्राधिकरण मे अनुमोदन प्रस्ताव निम्नानुसार है:–

(राशि लाखों में)

क्रं. सं.	राशि जहां से ली जानी				क्रं. सं.	राशि जहां को जानी हैं।				विशेष विवरण
	बजट शीर्षक	उपलब्ध प्रावधान	पुनर्विनियोजन की जाने वाली राशि घटाई गई	शेष प्रावधान		बजट शीर्षक	उपलब्ध प्रावधान	पुनर्विनियोजन किये जाने से प्राप्त राशि जोडी गई	योग	नया लेखाशीर्षक खोला गया
1	5005–06 –000(09)	1000.00	950.00	50.00	1	5005–06–000(06)	200.00	950.00	1150.00	

उपरोक्तानुसार पुनर्विनियोजन प्राधिकरण में अनुमोदन की प्रत्याशा में किया गया है, अतः प्राधिकरण में अनुमोदन हेतु एजेण्डा प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

तत्पश्चात् बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(यह बैठक कार्यवाही विवरण पत्रावली (बैठक शाखा/2020/भाग–9 प्राधिकरण की बैठक निर्धारण पत्रावली) के पैरा संख्या 210 /एन. में अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुमोदित है)

(उल्लेखनीय है कि जोधपुर विकास प्राधिकरण (कार्य संचालन) विनियम, 2014 के नियम 12 (2) में प्रावधान है कि यदि बैठक में उपस्थित पचास प्रतिशत या इससे अधिक सदस्य कार्यवृत्त प्राप्ति के सात दिवस के भीतर किसी विशिष्ट विनिश्चय या विनिश्चयों का कार्यवृत या उसके किसी भाग के गलत तथा/या त्रुटिपूर्ण अभिलेखन के आधार पर आपत्ति करें और निवेदन करे कि उक्त विनिश्चय या विनिश्चयों का कियान्वयन रोक दिया जावेगा और अगली बैठक में ऐसे विनिश्चय लिये जाने तक कियान्वित नहीं किया जावेगा। यदि उपस्थित सदस्यों के पच्चीस प्रतिशत या इससे अधिक किन्तु पचास प्रतिशत से कम सदस्य उपयुक्त रूप से किसी विनिश्चय या विनिश्चयों पर आपत्ति करें और उसके या उनके प्रवर्तन को रोकने के लिए निवेदन करें तो अध्यक्ष, यदि वह उचित समझे, अगली बैठक तक, जब प्रश्न विनिश्चय के लिए रखा जायेगा, कियान्वयन रोक सकेगा। यदि उपस्थित सदस्यों के बीस प्रतिशत से कम सदस्य उपयुक्त रूप से किसी विनिश्चय या विनिश्चयों पर आपत्ति करें तो उनकी आपत्ति या आपत्तियां विनिश्चय के लिए अगली बैठक में रखी जावेगी। कार्यवृत्त जब तक कि रोक या उलट न दिया गया हो, संशोधन या उपान्तरित न कर दिया गया हो, पीठासीन सदस्य तथा सचिव के हस्ताक्षरों के पश्चात् पुष्ट किया हुआ समझा जायेगा। परन्तु विनिश्चयों में ऐसे उपान्तरण, संशोधन या उनके उलटे जाने से विनिश्चय या विनिश्चयों में ऐसे उपान्तरण/संशोधन या उनके उलटे जाने से पूर्व की गई किसी बात या कार्यवाही पर किसी भी तरह का प्रभाव नहीं पडेगा)

13/4/22

(हरभान मीणा)
सचिव

कमांक/बैठक/2020/भाग(9)/1025-1044 दिनांक :: 13 अप्रैल, 2022

प्रतिलिपि वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1– प्रमुख शासन सचिव महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर
2– महापौर (उत्तर/दक्षिण) महोदया, नगर निगम, जोधपुर
3– जिला प्रमुख महोदया, जिला परिषद, जोधपुर
4– जिला कलक्टर महोदय, जोधपुर
5– उपाध्यक्ष, राजस्थान स्टेट रियल एस्टेट डवलपमेन्ट काउंसिल (आरएजेआरईडीसीको), 307, पिंक टॉवर, नेहरू गार्डन के सामने, टोंक रोड, जयपुर
6– संयुक्त शासन सचिव–तृतीय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर
7– आयुक्त, नगर निगम–उत्तर/दक्षिण, जोधपुर
8– अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, जोधपुर
9– मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, जोधपुर
10– प्रबन्ध निदेशक, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
11– उप आवासन आयुक्त–प्रथम/द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर

12– वरिष्ठ नगर नियोजक / उप नगर नियोजक, जोधपुर जोन, जोधपुर
13– निजी सचिव (अध्यक्ष महोदय / आयुक्त महोदय), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
14– निदेशक– अभियांत्रिकी / आयोजना / वित्त / विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
15– उपायुक्त–पूर्व / पश्चिम / उत्तर / दक्षिण / मुख्यालय, उप सचिव, भूमि अवाप्ति अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
16– अधीक्षण अभियन्ता–प्रथम / द्वितीय / तृतीय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
17– एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उप निदेशक) जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को आवश्यक कार्यवाही एवं वेबसाईट पर प्रदर्शन हेतु।
18– सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
19– ....

13/4/22

(हरभान मीणा)
सचिव

परिशिष्ट–1

श्री (डॉ.) राजेश शर्मा, आई.ए.एस., संभागीय आयुक्त एवं अध्यक्ष महोदय, जोधपुर की अध्यक्षता में प्राधिकरण कार्यालय स्थित उनके कक्ष में दिनांक 13 अप्रैल, 2022 को प्रातः 11.00 बजे आयोजित प्राधिकरण की बैठक में उपस्थित सदस्य/अधिकारियों का विवरण

1. श्रीमती कुंती परिहार देवडा, महापौर (उत्तर), नगर निगम, जोधपुर
2. सुश्री वनिता सेठ, महापौर (दक्षिण), नगर निगम, जोधपुर
3. श्री (डॉ) इन्द्रजीत यादव, आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
4. श्री प्रमोद टाक, प्रबन्ध निदेशक, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (डिस्कॉम) जोधपुर
5. श्री अरूण कुमार पुरोहित, आयुक्त, नगर निगम–दक्षिण, जोधपुर
6. श्री डा. बजरंग सिंह, अतिरिक्त आयुक्त, नगर निगम–उत्तर, जोधपुर
7. श्री डी.एस. चौहान, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर
8. श्री हेमेन्द्र नागर, अतिरिक्त कलक्टर–तृतीय, जोधपुर
9. श्री जे.सी. व्यास, अधीक्षण अभियन्ता–नगर वृत, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जोधपुर
10. श्री राकेश माथुर, अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर
11. श्री करणराज जीनगर, उप आवासन आयुक्त–प्रथम एवं द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर
12. श्री हरमान मीणा, सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर